part of the world. The details in th regard are being finalised.

संचरण एवं वितरण हानि में कमी

233. **श्री रामजेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत के संचरण एवं वितरण हानि में कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में तथा अन्त में कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत संचरण एवं वितरण हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रकार की हानि में कमी करने के लिए वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी हानियों में और कमी लायी जा सकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में कम से कम 01 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में 5 प्रतिशत तक की कुल कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1991-92) की शुरूआत में पारेषण एवं वितरण हानियां 22.83% थी और वर्तमान संकेतों के अनुसार यह लगभग 20% होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) यह देखा गया है कि देश में विद्यमान विद्युत प्रणाली में, उपयुक्त तकनीकी एवं प्रशासनिक उपायों द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में लगभग 10-15% तक की कमी लाई जा सकती है। तथापि, चूंकि वितरण संबंधित राज्य बिजली बोर्डों के अधिकार-क्षेत्र में आता है, इसलिए यह निश्चित करने के लिए पारेषण एवं वितरण के दौरान उनकी प्रणाली में किस सीमा तक विद्युत की कमी को रोका जा सकता है, उन्हें आवश्यक कदम उठाने होंगे।

Assistance Provided by IDBI

234. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the loan/assistance sanctioned by IDBI together with the recovery in each of the years from 1991 to 1994-95;

(b) the cumulative amount outstanding against loan/assistance during the same period;

(c) what is the amount which had become overdue during the period and the number of parties which had overdue amount exceeding rupees one crore each; and

(d) the name of industrial or other undertakings financed by IDBI where loans advanced have become irrecoverable and what has been done in these cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that the details of assistance sanctioned, outstanding and recovery under its direct finance schemes for each of the financial years from 1991-